



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 14, 2006/आषाढ़ 23, 1928

No. 158]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 14, 2006/ASADHA 23, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2006

(मध्यावधि समीक्षा)

विषय: सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ से फेनॉल के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों के संबंध में मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरुआत।

सं. 15/4/2006-डी जी ए डी.—यतः 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण), नियमावली 1995 (जिसे एतदपश्चात पाटनरोधी नियम कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने दिनांक 13/2/2003 की अधिसूचना संख्या 14/4/2002-डी जी ए डी के अनुसार सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ (जिन्हें एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फेनॉल (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात के संबंध में निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए उसके अंतिम जांच परिणाम को अधिसूचित किया था।

और यतः दिनांक 24/3/2003 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 47/2003-सीमाशुल्क के अनुसार

संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. विचाराधीन उत्पाद

विचाराधीन उत्पाद सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ के मूल का अथवा वहां से निर्यातित फेनॉल है। फेनॉल एक आधारभूत कार्बनिक रसायन है जिसको सामान्यतः सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत किया जाता है। उत्पाद का विपणन दो स्वरूपों में किया जाता है - खुले तथा पैक स्वरूप में। खुले में बिक्री सामान्यतः अत्यधिक मात्रा में की जाती है, जबकि पैक किए हुए परेषण काफी छोटे आकार के कंटेनर लोड के होते हैं। फेनॉल का उपयोग फेनॉल फॉर्मैल्डिहाइड रेजिन्स, लैमिनेट्स, प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड्स, बिसफेनॉल-ए, एल्किल फेनॉल्स, फार्मास्युटिकल्स, डाईफेनिल ऑक्साइड इत्यादि में किया जाता है। इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष सं० 2907.11 एवं भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार 2707.60 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि सीमाशुल्क और आई टी सी एच एस वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

3. जांच शुरुआत

सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाई गई निहित पाटनरोधी नियमावली के अनुसार पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा की जानी अपेक्षित है। मै० हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और शेनेक्टेडी हर्डिलिया लि० ने सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा की आवश्यकता का प्रमाण देते हुए एक याचिका दायर की है और ऊपर उल्लिखित अधिसूचनाओं के तहत संबद्ध वस्तुओं पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क में वृद्धि/संशोधन का अनुरोध किया है। याचिकाकर्त्ताओं ने लागू उपायों के वर्तमान स्वरूप, जो शुल्क का परिवर्तनीय स्वरूप है, को निश्चित पाटनरोधी शुल्क में परिवर्तित करने का अनुरोध किया है। निर्दिष्ट अधिकारी का मानना है कि उपर्युक्त नियम के नियम 23 के प्रावधानों के तहत इस स्तर पर सिफारिश किए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि जांच करना उचित होगा।

4. शामिल देश

वर्तमान जांच में शामिल देश सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ हैं ।

5. प्रक्रिया

घरेलू उद्योग द्वारा दिनांक 13/2/2003 की सं० 14/4/2002-डी जी ए डी द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम तथा दिनांक 24/3/2003 की अधिसूचना संख्या 47/2003 - सीमाशुल्क द्वारा लागू अंतिम शुल्क की समीक्षा हेतु उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर पूर्णतः संतुष्ट होने के बाद प्राधिकारी, इस बात की जांच करने के लिए कि क्या सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और पाटनरोधी नियम के अनुसार वर्तमान स्वरूप में पाटनरोधी शुल्क को लगातार और शुल्क की वर्तमान सीमा तक लागू रखना आवश्यक है अथवा नहीं, समीक्षा करने हेतु एतद्वारा जांच की शुरुआत करते हैं ।

समीक्षा में दिनांक 13/2/2003 की अधिसूचना सं० 14/4/2002-डी जी ए डी के सभी पहलू शामिल हैं ।

6. जांच की अवधि

वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 जुलाई, 2005 से 31 मार्च, 2006 है । तथापि, क्षति जांच अवधि में जांच अवधि सहित वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 और 2005-06 की अवधि शामिल है ।

7. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों में निर्यातकों और भारत में स्थित उनके दूतावासों/प्रतिनिधियों के माध्यम से उनकी सरकारों, भारत में उनके ज्ञात संबद्ध आयातकों और प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को संगत सूचना,

निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से प्रस्तुत करने और अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत कराने का अनुरोध किया गया है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी,

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,

वाणिज्य विभाग,

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डी जी ए डी)

कक्ष सं० 240, उद्योग भवन

नई दिल्ली-110011

अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकती है।

8. समय-सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुँच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों तथा आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर सूचना प्रस्तुत करनी होगी।

9. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं। यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है।

क्रिस्टी एल. फेर्नान्डेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2006

(Mid-Term Review)

Subject: Initiation of mid term review investigation with regard to the anti-dumping duties in force involving the imports of Phenol from Singapore, South Africa And European Union

No. 15/4/2006-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after referred to as AD Rules), vide Notification No. 14/4/2002-DGAD dated 13.2.2003, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) notified its final findings recommending definitive anti dumping duty on import of Phenol (herein after referred to as subject goods) originating in or exported from Singapore, South Africa And European Union (hereinafter referred to as subject countries).

And whereas definitive antidumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 47/2003-Customs, dated 24.3.2003.

2. Products under consideration

The product under consideration is Phenol originating in or exported from Singapore, South Africa And European Union. Phenol is a basic organic chemical normally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. The product is marketed in two forms - loose and packed. Loose sales are normally in bulk, whereas packed consignments can be of much smaller container loads. Phenol is used in Phenol Formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, Particle Boards, Bisphenol-A, Alkyl Phenols, Pharmaceuticals, Diphenyl Oxide etc. This product is classified under Customs Tariff heading no. 2907.11 and 2707.60 as per Indian Trade Classification. The Customs and ITC HS classifications are, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation

3. Initiation

The Customs Tariff (Amendment) Act 1995 and the Anti Dumping Rules made there under require the Authority to review from time to time the need for continuance of anti-dumping duty. M/s. Hindustan Organic Chemicals Limited and Schenectady Herdillia Limited have filed a petition substantiating the need for mid term review of the anti-dumping duty imposed on the subject goods originating in or exported from Singapore, South Africa and European Union and have requested for enhancement/revision of the anti-dumping duty imposed on subject goods under the above mentioned notifications. The

2160GI/C6-2

Petitioners have also requested for modification of the form of measures from the present form, which is variable form of duty to fix form of anti dumping duty. The Designated Authority considers that mid term review of the anti dumping duty recommended would be appropriate at this stage under the provisions laid down in Rule 23 of the Rules supra.

4. Countries involved:

The Countries involved in the present investigation are Singapore, South Africa and European Union.

5. Procedure

Having satisfied itself on the basis of evidence submitted by domestic industry for review of the final findings notified vide No. 14/4/2002-DGAD dated 13.2.2003 and final duty imposed by Notification No. 47/2003-Customs, dated 24.3.2003, the Authority hereby initiates investigations to review whether continued imposition of anti dumping duties in the present form and to the present extent of duty is necessary in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Anti Dumping Rules.

The review covers all aspects of Notification No. 14/4/2002-DGAD dated 13.2.2003.

6. Period of investigation (POI):

The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st July, 2005 to 31st March, 2006. The injury investigation period will however, cover the period 2002-03, 2003-04, 2004-05 and 2005-06 including the period of investigation.

7. Submission of information:

The exporters in the subject countries and their government through their embassies/ representatives in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are requested to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

The Designated Authority,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties, (DGAD),
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi-110011

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

8. Time limit

Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty (40) days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within (40) forty days from the date of the letter addressed to them.

9. Inspection of public file

In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

CHRISTY L. FERNANDEZ, Designated Authority